हिन्दुस्तान
पटना • रविवार • 21 जुलाई 2013
02

अफसरों को ट्रेनिंग देगा ग्रामीण विकास विभाग

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

ग्रामीण विकास विभाग के तहत चलने वाली तमाम कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी स्तर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने जा रहा है। इन केन्द्रों का नाम एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर (ईटीसी) रखा गया है। सभी प्रमंडल में केन्द्र स्थापित करने के लिए विभाग ने डीडीसी को स्थान का चयन करने के लिए लिखा है।

फिलहाल इन केन्द्रों को किसी सरकारी भवन में शुरू किया जाएगा। भवन ऐसे होने चाहिए, जिसमें क्लास रूम के लिए दो कमरे, एक हाल और कार्यालय कार्य के लिए दो कमरे होने चाहिए। इसे एक समेकित संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

जिन प्रमंडलीय मुख्यालयों में ईटीसी की स्थापना की जाएगी, उसमें गया, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, छपरा, सहरसा और पूर्णिया शामिल हैं। इसमें सारण, सहरसा और पूर्णिया जिलों ने स्थान का चयन कर इसकी सूचना विभाग को दे दी है। अन्य जिलों ने स्थान का चयन नहीं किया है। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि ईटीसी को एक सशक्त सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी स्तर के पदाधिकारियों को जरूरी ट्रेनिंग दी जा सके। विभाग ने इसकी पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है। ये सेंटर जल्द ही शुरू हो जाएंगे।

मनरेगा साफ्ट में होंगे कई बदलाव

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

दूर होगी परेशानी

- मनरेगा की मॉनिटरिंग व अपडेट स्थिति की जानकारी देने के लिए मनरेगा सॉफ्ट तैयार
- राज्य का ग्रामीण विकास विभाग भेजेगा केन्द्र को सुझाव

मनरेगा की मॉनिटरिंग और अपडेट स्थिति की जानकारी देने के लिए मनरेगा सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर तैयार है। यह प्रणाली केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट से लिंक है। इसमें मनरेगा योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां अपलोड रहती हैं। इसका संचालन केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग करता है। इस सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रभावी और अपडेट बनाने के लिए राज्य ग्रामीण विकास विभाग ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग को कई बिन्दुओं पर सुझाव भेजा है। इससे पहले विभाग ने इस मामले में सभी डीडीसी से भी सुझाव मंगवाया था।

विभाग ने चार महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं, जिसके तहत सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल में बदलाव करने की जरूरत बतायी गई है। साथ ही इसका वर्षवार खाता मेंटेन करने की व्यवस्था करने को कहा गया है। मनरेगा योजना के तहत पौधरोपण योजना को मनरेगा सॉफ्ट पर अपडेट करने की सुविधा नहीं है। वर्तमान में इसे तीन साल पर अपडेट करने की व्यवस्था है। इससे इस योजना के क्रियान्वयन में काफी परेशानी होती है।

इसके अलावा मनरेगा सॉफ्ट में अभी महादलितों का कोई कॉलम नहीं है। अभी सिर्फ एससी-एसटी का ही कॉलम है। इस वजह से महादलितों को किस जिला या पंचायत में कितना काम मिला, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। महादलितों के लिए अलग से कॉलम बनाने का सुझाव दिया गया है। किस पंचायत को कितने पैसे मिले हैं, इस फंड फ्लो का हिसाब अभी पता नहीं चला पाता है।